आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)

शुक्रवार 26.09.2025 समय 1305

मुख्य समाचार :–

- आईसीयू सेवाओं की गुणवत्ता और मानक तय करने के लिए उत्तराखंड में बड़ी पहल। स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
- प्रदेश की सहकारी समितियों में शीघ्र ही 279 कैडर सचिवों की भर्ती की जाएगी।
- राज्य में 'स्वस्थ नारी–सशक्त परिवार' अभियान के तहत आयोजित किए जा रहे स्वास्थ्य शिविरों में अब तक 6 लाख 59 हजार से अधिक लोगों ने लाभ उठाया।
- अल्मोड़ा में पीएम स्वनिधि पुनर्गठित योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के संदर्भ में कार्यशाला का आयोजन।

आईसीयू सेवाएं

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उत्तराखंड सरकार ने राजकीय और निजी अस्पतालों में आईसीयू सेवाओं को लेकर गंभीर पहल शुरू की है। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के विशेषज्ञों के साथ मिलकर आईसीयू संचालन के मानक और गुणवत्ता सुधार के लिए विस्तृत सुझाव तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आईसीयू संचालन से संबंधित वर्तमान गाइडलाइन को और प्रभावी बनाने के लिए स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में देहरादून में महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान प्रदेश के राजकीय और निजी मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सालयों के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने आईसीयू के मानकों पर विस्तार से चर्चा की। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि इस कार्यशाला से प्राप्त सुझावों को संकलित कर सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाएगा। इससे न केवल आईसीयू संचालन के मानकों को और बेहतर बनाया जा सकेगा, बल्कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित सेवाएं भी उपलब्ध होंगी।

कैडर सचिव भर्ती

प्रदेश के सहकारी विभाग के अंतर्गत संचालित सहकारी समितियों में शीघ्र ही 279 कैडर सचिवों की भर्ती की जाएगी। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने देहरादून में में विभाग की समीक्षा बैठक में सहकारी समितियों में लम्बे समय से रिक्त 279 कैडर सचिवों की शीघ्र भर्ती करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कैडर सचिवों की नियुक्ति से प्राथमिक सहकारी समितियों में पारदर्शिता के साथ काम होंगे। साथ ही समितियां आर्थिक रूप भी मजबूत होंगी। इसके अलावा समितियों के कार्यों में तेजी आयेगी, जिससे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को प्रत्यक्ष लाभ मिल सकेगा। बैठक में सहकारिता मंत्री ने अन्तरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में आगामी तीन अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक प्रदेशभर में विशेष थीम पर आधारित सहकारी मेलों के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा भी की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने उत्तराखंड आवास एवं निर्माण सहकारी संघ के कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने आवास संघ के तहत संचालित विभिन्न निर्माण कार्यों को प्रगति की जानकारी लेते हुए विभागीय अधिकारियों को सभी निर्माण कार्यों को पारदर्शिता व गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।

मानक महोत्सव

विश्व मानक दिवस–2025 के उपलक्ष्य में भारतीय मानक ब्यूरो, बीआईएस, देहरादून शाखा द्वारा हरिद्वार में मानक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उद्योगों के प्रतिनिधियों, ज्वैलर्स, स्कूली छात्रों, सरकारी विभागों के अधिकारियों और आमजन ने भाग लिया। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि प्रत्येक उत्पाद, मानकों के अनुरूप ही निर्मित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सभी हितधारकों को मिलकर कार्य करना होगा। बीआईएस देहरादून शाखा के निदेशक व प्रमुख सौरभ तिवारी ने कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा

बीआईएस विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हितधारकों को जोड़कर मानकों के महत्व के प्रति जागरूक कर रहा है।
कार्यक्रम में मानक संवर्द्धन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले मेंटर्स, उद्योगों, ज्वैलर्स और रिसोर्स पर्सन्स को सम्मानित भी किया गया।

स्वस्थ नारी–सशक्त परिवार

प्रदेश में 'स्वस्थ नारी–सशक्त परिवार' अभियान के तहत आयोजित किए जा रहे स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से लोगों की प्राथमिक जांच, लक्षित स्क्रीनिंग, टीकाकरण और परामर्श सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं।

17 सितम्बर से शुरू हुआ 'स्वस्थ नारी–सशक्त परिवार' महाअभियान आगामी दो अक्टूबर तक जारी रहेगा। प्रदेश में अब तक 12 हजार से अधिक शिविरों के जरिए 6 लाख 59 हजार से ज्यादा लोग, लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वस्थ नारी– सशक्त परिवार अभियान प्रदेश की सामाजिक व आर्थिक मजबूती के लिए निर्णायक पहल है। इतने कम समय में हजारों शिविरों के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंच बनना यह दर्शाता है कि स्वास्थ्य सेवा अब घर–घर तक पहुँचाने योग्य है। उन्होंने कहा कि मातृत्व स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य और बुजुर्गों की देखभाल में निरंतर सुधार लाने के साथ ही दुर्लभ व लक्षित बीमारियों की शीघ्र पहचान कर इलाज सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि यह अभियान स्वास्थ्य व्यवस्था के हर स्तर को मजबूत कर रहा है। उन्हेंने कहा कि स्क्रीनिंग, टीकाकरण और परामर्श सेवाओं के विस्तार से न केवल रोगों का शीघ्र पता चल रहा है, बल्कि इलाज की दिशा में लोगों में बढ़ती जागरूकता भी मिल रही है।

इस व्यापक पहल का उद्देश्य महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जल्दी पहचान, समय पर उपचार और रोगनिवारक सेवाओं का स्थायी नेटवर्क बनाना है, ताकि हर नागरिक सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और जवाबदेह स्वास्थ्य सुविधाओं से लाभान्वित हो सके।

कार्यशाला

नगर निगम अल्मोड़ा द्वारा पीएम स्वनिधि पुनर्गठित योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के संदर्भ में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में फड़ व्यवसायियों और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने भाग लिया। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की शहरी प्रबंधक शांता गुरुरानी ने कहा कि पीएम स्वनिधि पुनर्गठित योजना का उद्देश्य फड़ व्यवसायियों और महिला समूहों को आत्मनिर्भर बनाना, आजीविका संवर्धन, वित्तीय समावेशन और डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रोत्साहन देना है।

अभिनय कार्यशाला

उत्तराखंड के सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के महानिदेशक और उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के सीईओ बंशीधर तिवारी ने कहा है कि राज्य में फिल्म शूटिंग के लिए बेहतर माहौल है। फिल्म उद्योग को प्रोत्साहन मिल रहा है और अन्य राज्यों की तुलना में प्रदेश सरकार की ओर से अनुदान धनराशि भी ज्यादा दी जा रही है। श्री तिवारी सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में नेक्स्ट लेवल एवं संभव कला मंच की ओर से आयोजित पांच दिवसीय अभिनय कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और उन्हें बेहतर मंच देने की जरूरत है। फिल्म विकास परिषद की ओर से अभिनव पहल करते हुए इस प्रकार की कार्यशाला की शुरूआत की गई है।

रेल–आधारित मोबाइल लॉन्चर

भारत ने रेल–आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से मध्यम दूरी की अग्नि–प्राइम मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है। उन्नत सुविधाओं से लैस अगली पीढ़ी की इस मिसाइल की मारक क्षमता दो हजार किलोमीटर है। यह अपनी तरह का पहला प्रक्षेपण है जिसे विशेष रूप से निर्मित रेल–आधारित मोबाइल

लॉन्चर से प्रक्षेपित किया गया। इससे उपयोगकर्ता को कम दृश्यता और कम समय में प्रक्षेपण करने की सुविधा मिलती है। अब भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास चलते–फिरते रेल नेटवर्क से कैनिस्टराइज्ड प्रक्षेपण प्रणालियाँ विकसित करने की क्षमता है।